(च) क्या सरकार ने विद्युत की आपूर्ति में कमी को मद्दे नजर रखते हुए विद्युत की खपत में कटौती करने के लिए क्षेत्रों का पता लगा लिया है; और

(छ) यदि हां, तो विद्युत की खपत में कहां-कहां और कितनी-कितनी कटौती करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय हेतु वर्ष 1992-93 के लिए 5167.00 करोड़ रु. के योजना परिव्यय की तुलना में उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार वास्तविक समुपयोजन 3602.13 करोड़ रु. था।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1992-93) के दौरान वास्तविक क्षमता संवर्धन उपलब्धि 3537.27 मे. वा. रही है जबकि कार्यक्रम 4458.02 मे. वा. का था।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में प्रत्याशित विद्युत शृंखलाई स्थिति निम्नानुसार है :—

ऊर्जा (मि० यू०)		व्यस्ततमकालीन (मे० वा०)	
आवश्यकता	327290	व्यस्ततमकालीन मांग	56000
उपलब्धता	294620	व्यस्ततमकालीन उपलब्धता	44200
कमी	32670	व्यस्ततमकालीन कमी	11800
ऊर्जा कमी (%)	9.98	व्यस्ततमकालीन कमी (%)	21.1

(च) और (छ) विद्युत की मांग को इसकी उपलब्धता के संगत बनाए रखने के लिए राज्यों द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं के मामले में विद्युत कटौतियों/प्रतिबन्धों का सहारा लेना पड़ता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित मामले

211. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1991 से, विभागीय सतर्कता विभाग के पास दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कार्यरत प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लगभग 300 मामले जांच के लिए लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो 1991 से, उक्त संस्थान में कार्यरत द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुल कितने मामले सतर्कता विभाग के पास जांच के लिए लम्बित हैं;

(ग) क्या प्रशासन में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उक्त सभी मामलों की शीघ्र जांच करने के बाद दोषी व्यक्तियों को दण्ड देना आवश्यक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सतर्कता विभाग के काम काज में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ताकि वह विभाग एक निर्धारित अवधि में भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा कर सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो 1991 से जांच के

लिए लम्बित मामलों के निपटारे के लिए सरकार ने कितनी अवधि निर्धारित की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Construction of Thermal Power Projects in Northern States

212. SHRI DIGVIJAY SINGH :
SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA :

Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct thermal projects in Northern States, particularly in Bihar and in Uttar Pradesh with the help of foregin collaboration/Private sector;

(b) if so, what are the details thereof stating the names and places of such State and the time by which the work is likely to be taken up;

(c) what would be the esitmated amount to be invested thereon;

(d) whether any foreign offer or any private sector offer has been received by Government till date to establish high generating power plant;

(e) if so, the details thereof stating the names of such concern; and

(f) the quantum of power likely to be produced by the project ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) to (f) Intendments received from private Companies, both Indian and foreign (including NRIs), in the States in the Northern Region are given in the Statement (See below). The time schedule of implementation of these projects would be known after the various inputs and clearances have been tied up.

Statement

Annexure referred in reply to Rajya Sabha USQ. No. 212 for 27-4-1993 by Shri Digvijay Singh and Shri Satya Prakash Malvia regarding Construction of Thermal Power Projects in Northern States.

Sl. No.	Name of Project/ States	Foreign/ Indian	Capacity (MW)	Approx. Cost	Name of the Company
1	2	3	4	5	6
				(Rs. Crs.)	
Bihar					
1.	Chandil TPS	Indian	500.00 (2x250) (Coal)	1637.00 (Apr. 92)	RPG Enterprises
Haryana					
2.	Hissar TPS	Foreign	500.00 (2x250) (Coal)	1000.00	Cogentrix Inc. USA
Himachal Pradesh					
3.	Ghanvi HEP	Indian	22.50 (Hydro)	40.00	Punjab Power Generation Machines Ltd.